पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

की चौथी तिमाही व वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सम्मेलन

30 मई, 2017

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)	Prabhudas Lilladher POWERING YOUR FINANCIAL GROWTH

– प्रबंधन

– पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की टीम :

– श्री राजीव शर्मा	–	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
– श्री आर. रंगराजन	–	निदेशक (वित्त)
– श्री डी. रवि	–	निदेशक (वाणिज्य)
– श्री सी. गंगोपाध्याय	–	निदेशक (परियोजना)
– संचालक	–	श्री आर. श्रीशंकर
	–	प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड

– **श्री आर. श्रीशंकर – प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड**

– सुप्रभात, देवियों और सज्जनों। आप सभी का 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के परिणामों के बारे में प्रभुदास लीलाधर की ओर से बुलाए गए सम्मेलन में स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नागराजन, निदेशक वित्त, श्री रवि, निदेशक वाणिज्य, और श्री सी. गंगोपाध्याय, निदेशक परियोजना। उपस्थित समस्त सज्जनों का स्वागत है और इस आह्वान पर यहां उपस्थित होने के लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आमंत्रित करता हूं। श्री राजीव शर्मा आगे की कार्यवाही संभालने की कृपा करें।

– **श्री राजीव शर्मा**

– सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का इस तिमाही और 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों पर आयोजित किए गए सम्मेलन आह्वान में स्वागत करता हूं।

– सबसे पहले, मैं आपके साथ, हमारे लाभ के कारणों और वित्त वर्ष 2016–17 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2016–17 के मंद पड़ चुके अन्य वित्तीय मापदंडों को साझा करना चाहता हूं।

– पीएफसी द्वारा 01 अप्रैल, 2015 से नए बिजली उत्पादन ऋणों की मंजूरी पर आरबीआई के पुनर्गठन मानकों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, 01 अप्रैल, 2015 से पहले मंजूर बिजली उत्पादन ऋणों पर, पीएफसी द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन मानकों का पालन किया जा रहा है।

– हालांकि, पुनर्गठन मानकों के बारे में काफी पत्राचार करने और आरबीआई के दिशानिर्देशों की प्राप्ति के बाद, हमने 01 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी प्रभाव से आरबीआई के पुनर्गठन मानकों का पालन करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, इस तिमाही और वर्ष के दौरान हमारा लाभ और अन्य वित्तीय परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

– आरबीआई मानकों का पालन करने के कारण, लगभग 59,000 करोड़ रुपये की ऋण परिसंपत्तियों का मूल्य कम हो गया है, जिसमें से 36,000 करोड़ रुपये कम होकर पुनर्गठित हो गए हैं और 23,000 करोड़

रुपये गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गए हैं। इसके कारण लाभ पर पड़ने वाला कुल भार लगभग 3,786 करोड़ रुपये है।

– 59,000/– करोड़ रुपये की कुल प्रभावित परिसंपत्तियां

(1) राज्य सरकार या केंद्र सरकार–सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम से संबंधित हैं और बिजली उत्पादन परियोजनाएं हैं।

(2) सरकारी क्षेत्र के सभी कर्जदार नियमित रूप से हमारी देय राशि का भुगतान कर रहे हैं, जिसकी वसूली दर वित्त वर्ष 2016–17 में 100 प्रतिशत है अर्थात 31 मार्च, 2017 की स्थिति को कोई देय बकाया नहीं था (मेघालय के 4 करोड़ रुपये के अलावा जिसकी अदाएगी 31 मार्च, 2017 के बाद कर दी गई है।)

– अब मैं उन लेखों का ब्योरा दे रहा हूं, जो आरबीआई मानकों के कारण प्रभावित हुए हैं।

– सबसे पहले, 4.25 प्रतिशत की व्यवस्था के साथ ऋण परिसंपत्तियां घटकर पुनर्गठित हो गई हैं,

– 36,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां मानक से घटकर पुनर्गठित हो गई हैं, जिसका 1,404 करोड़ रुपये के लाभ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस पुनर्गठित परिसंपत्ति में से :–

  – 58 प्रतिशत या 20,890 करोड़ रुपये पहले ही लगाए जा चुके हैं और वित्त वर्ष 2018–19 में यह रिवर्स हो जाएगा।

  – 31 प्रतिशत या 11,165 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2017–18 में लगाए जाएंगें।

  – 10 प्रतिशत या 3,670 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018–19 में लगाए जाएंगें।

  – 1 प्रतिशत या 270 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019–20 में लगाए जाएंगें।

  इसी तरह, मेरा कहना है कि सभी पुनर्गठित परिसंपत्तियां राज्य सरकार या केंद्रीय ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की हैं और सभी ऋणों का नियमित भुगतान हो रहा है (अर्थात वसूली दर 100 प्रतिशत है)।

– दूसरा, 10 प्रतिशत की व्यवस्था के साथ ऋण परिसंपत्तियां घटकर गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां बन चुकी हैं।

- 23,300 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां घटकर गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां बन गई हैं, जिसका इन गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों के लाभ पर 2,382 करोड़ रुपये का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- सभी परियोजनाएं राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन परियोजनाएं हैं और इनके पास ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और बिजली खरीद करार (पीपीए) हैं और 100 प्रतिशत की वसूली के साथ इनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

  - 79 प्रतिशत या 18,504 करोड़ रुपये को वित्त वर्ष 2017–18 में अपग्रेड मिलेगा, जिसमें से

  - 68 प्रतिशत या 15,883 करोड़ रुपये को पहले ही सीओडी मिल चुका है।

    - 2 प्रतिशत या 525 करोड़ रुपये सीओडी मिलेगा।

    - 9 प्रतिशत या 2,096 करोड़ रुपये प्राप्त किए जाने हैं और पुनर्गठित श्रेणी में अपग्रेड हो जाएंगे।

    - 19 प्रतिशत या 4,494 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018–19 में अपग्रेड होकर मानक हो जाएंगे।

    - 1 प्रतिशत या 332 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2019–20 में अपग्रेड होकर मानक हो जाएंगे।

- आरबीआई मानकों के कारण प्रभावित हुए 59,000 करोड़ रुपये की इन ऋण परिसंपत्तियों में कोई दिक्कत नहीं है और अगले पांच वर्षों में ये मानक बन जान की संभावना है। गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों का 80 प्रतिशत चालू वर्ष अर्थात 2017–18 में ही अपग्रेड हो जाएगा।

- इसके अलावा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, सरकारी कर्जदारों को कभी भी गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां घोषित नहीं किया गया (सिक्किम पावर जो अब मानक है और रत्नागिरी के सिवाए जो एनपीपीसी और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है)।

- इस वर्ष लाभ पर प्रभाव डालने वाले अन्य कारक हैं:–

- आरकेएम पावरजेन की मानक परिसंपत्तियों की आय में 413 करोड़ रुपये रिवर्स हो जाना।

– यूडीएवाई पूर्वभुगतानों के कारण 225 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर भार।

– इन दो मदों और आरबीआई का प्रभाव न पड़ा होता तो, हमारा लाभ 6,400 करोड़ रुपये होता।

– मैं यहां यह भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूं कि भले ही हमने निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर आरबीआई मानकों को भूतलक्षी प्रभाव से 01.04.2015 से लागू किया है, पर किसी भी निजी खाते को डाउनग्रेड नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि हम आमतौर पर निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन परियोजनाओं के संघीय निधिकरण के कारण आरबीआई के मानकों का पालन कर रहे हैं।

– अब मैं अपनी परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर आरबीआई के प्रभाव, बिना आरबीआई प्रभाव के बारे में बातें करुंगा।

– वास्तव में, वर्ष 2016–17 के दौरान, आरबीआई के प्रभाव के बिना, हमारी गैर–निष्पादक परिसंपत्तियां कम हो गई हैं।

– 920 करोड़ रुपये के 4 ऋण खाते अपग्रेड होकर मानक श्रेणी में आ गए हैं। (अलखनंदा हाइड्रो –560 करोड़ रुपये, आरएस इंडिया–230 करोड़ रुपये, सिक्किम पावर डिवेलपमेंट–97 करोड़ रुपये, एस्टन फील्ड – 32 करोड़ रुपये)

– 442 करोड़ रुपये की केवल 1 बिजली उत्पादन ऋण परिसंपत्ति कम होकर गैर–निष्पादक परिसंपत्ति हो गई है (इंड भारत मद्रास)।

इसके साथ, वर्ष 2016–17 के लिए गैर–निष्पादक परिसंपत्ति का औसत है

आरबीआई मानकों के साथ आरबीआई मानकों के बिना

सकल एनपीए – 12.50 प्रतिशत – 3.01 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 3.15 प्रतिशत से सुधार हुआ)।

निवल एनपीए – 10.55 प्रतिशत – 1.68 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 2.55 प्रतिशत से सुधार हुआ) ।

– जहां तक बकाया पुनर्गठित बही का सवाल है, तो आरबीआई मानकों के कारण प्रभावित होने वाली बहियों के अलावा यह 19,500 करोड़ रुपये है।

– 26 प्रतिशत या 5,000 करोड़ रुपये पहले ही लगाए जा चुके हैं और वर्ष 2017–18 में 4,500 करोड़ रुपये और 2018–19 में 500 करोड़ रुपये रिवर्स हो जाएंगे।

– इस पुनर्गठित बही का 70 प्रतिशत या 13,500 करोड़ रुपये वर्ष 2017–18 में ही अनुसूचित सीओडी हैं।

– 19,500 करोड़ रुपये की ये सभी पुनर्गठित बही निजी क्षेत्र की हैं।

– अब मैं अन्य वित्तीय तथ्यों की बात करुंगा। इस क्षेत्र में आई चुनौतियों के बावजूद भी हमने वर्ष 2016–17 के दौरान मजबूत कारोबारी वृद्धि दर्ज की है, जो निम्नलिखित के रूप में देखी जा सकती हैः–

– हमारी ऋण मंजूरी वृद्धि 55 प्रतिशत बढ़कर 65,042 करोड़ रुपये से 100,603 करोड़ रुपये हुई है।

– संवितरण वृद्धि 35 प्रतिशत बढ़कर 46,588 करोड़ रुपये से 62,798 करोड़ रुपये हुई है।

– इसके अलावा, वर्ष के दौरान 28,400 करोड़ रुपये के यूडीएवाई पूर्व–भुगतानों के बावजूद, सकारात्मक ऋण परिसंपत्ति वृद्धि दिखाने के लिए हमने अपने संवितरणों को बढ़ाया है।

– ऋण परिसंपत्ति 3 प्रतिशत बढ़कर 2,38,920 करोड़ रुपये से 2,45,525 करोड़ रुपये हो गई है।

– आरबीआई प्रभाव के बावजूद भी, हमने वर्ष के लिए 3.00 प्रतिशत का मजबूत स्तर और 4.54 की निवल ब्याज मार्जिन बनाए रखा है।

– संसाधन जुटाने के बारे में

– वर्ष के दौरान हमने लगभग 66,800 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिसकी अतिरिक्त लागत 7.47 प्रतिशत थी।

– आरबीआई की अपेक्षा के अनुसार, टियर 1 पूंजी के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की तुलना में हमारी पूंजी पर्याप्तता औसत 16.20 प्रतिशत की टियर 1 पूंजी के साथ 19.28 पर बनी हुई हुआ है।

– सरकार ने अपने संघीय बजट में 54ईसी पूंजी लाभ बॉड उगाहने के लिय अन्य कंपनियों को अनुमति देने का प्रावधान किया है। हमने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया है और हम

आशावान् हैं कि ये हमें मिल जाएंगे, जिससे वर्ष 2017–18 के दौरान हमारी निधियों की लागतों में कमी आएगी।

– आगे बढ़ता कारोबार–हमने नए क्षेत्रों/कारोबारी हिस्सों की पहचान कर ली है और बाजार में और हिस्सेदारी बढाने के प्रयोजन से कारोबारी वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने उत्पादों में परिवर्तन किया है, हम चालू वर्ष 2017–18 में भी संवितरणों में बढोतरी करना चाहते हैं।

– नवीकरणीय निधिकरण पर बढ़ता ध्यान :–

  – अनुमानों के अनुसार, अगले 4 से 5 वर्ष में बिजली क्षेत्र में मोटे तौर पर 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरुरत होगी, जिसमें से बहुत बड़ा निवेश नवीकरणीय क्षेत्र में किया जाएगा।

  – भारत सरकार का मिशन वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता तैयार करना है।

  – नवीकरणीय कारोबार को और आकर्षित करने के लिए पीएफसी ने प्रतिस्पर्धी शर्तों (कम ब्याज दर सहित) और संशोधित नीतियों जैसे कदम उठाए हैं।

  – हमने शीघ्र संवितरण के लिए ऋण पुनर्वित्तीयन/कमीशन परियोजनाओं की आकर्षक शर्तें पेश की हैं।

  – हम भारत सरकार की योजनाओं जैसे समेकित बिजली विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से काउंटरपार्ट निधिकरण कारोबार सहित पारेषण और वितरण कारोबार पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं।

  – सभी के लिए 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करना होगा :–

    – पीएफसी इस कारोबार के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है।

    – पीएफसी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए विद्यमान ऋणों का पुनर्वित्तीयन करना चाहता है।

    – इसके अलावा, हमारे बकाया ऋण मंजूरी 1.5 लाख करोड़ रुपये हैं।

– जो हमारे वार्षिक संवितरणों का 2.5 गुणा है।

– जो हमारी बढ़ती हुई मजबूत कारोबारी स्थिति को दर्शाता है।

– आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र शुरु कर सकते हैं।

– **संचालक**

– धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करेंगे। जो भी प्रश्न करना चाहता है वो अपने टच टोन टेलीफोन पर तारे वाले निशान को दबाए। यदि अपने प्रश्न पूछने के क्रम से हटना चाहते हैं तो, तारे का निशान और 2 दबाएं। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि प्रश्न पूछते समय हैंडसेट का इस्तेमाल करें।

– पहला प्रश्न सुंदरम म्युचुअल फंड के धवल गादा (Gada) का है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– **श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड**

– महोदय, मैं आपकी शुरुआती टिप्पणियों के कुछ हिस्सों को सुन नहीं सका। महोदय, क्या आप स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। सबसे पहले स्लाइड–2, 23,309 करोड़ रुपये को स्पष्ट करें, इसमें से कितना–कितना राज्य या केंद्रीय सरकार से संबंधित है।

– **श्री राजीव शर्मा**

– सभी सरकारी हैं, शत–प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं।

– **श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड**

– ठीक है महोदय। सकल एनपीए के अलावा तिमाही के दौरान कितनी स्लीपेज थी? कितनी वृद्धि हुई?

– **श्री राजीव शर्मा**

– 23,309 करोड़ रुपये में से। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारा सकल एनपीए 3.01 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष 3.15 प्रतिशत था, जो आरबीआई मानकों से प्रभावित हुए बिना सुधरकर 3.01 प्रतिशत हो गया। साथ ही, हमारा निवल एनपीए सुधरकर 1.68 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले वर्ष 2.55 था। आरबीआई मानकों के प्रभाव सहित हमारा सकल एनपीए 12.50 प्रतिशत और निवल एनपीए 10.55 प्रतिशत बैठता है।

– **श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड**

– ऐसा नहीं महोदय, यह बात मुझे पता है।

– **श्री राजीव शर्मा**

– 23,300 करोड़ रुपये एनपीए हो गए हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको उन परियोजनाओं और उन परियोजनाओं का नाम भी बता सकता हूं।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– यदि आप बता सकते हैं तो, सबसे बड़ी पांच परियोजनाओं के नाम बताएं जिससे इसके आकार और मात्रा के बारे में कुछ आभास हो पाए और किस बात की निगरानी करनी होगी।

– श्री राजीव शर्मा

– पहली, छत्तीसगढ़ में 2 x 500 मेगावाट की मारवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 और 2 है, जिसे जुलाई, 2016 में ही शुरु किया जा चुका है और यह 15 अक्तूबर, 2017 तक चालू हो जाएगी। दूसरी, 2 x 500 मेगावाट की मालवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। सीओडी 28 दिसंबर, 2014 तक पहले ही प्राप्त कर लिया गया था और यह 15 अक्तूबर, 2017 तक चालू हो जाएगी।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– महोदय, इनकी राशि बताने की कृपा करें।

– श्री राजीव शर्मा

– पहली परियोजना की राशि 7,112 करोड़ रुपये है, जो पहले ही शुरु हो चुकी है और 15 अक्तूबर, 2017 तक अपग्रेड हो जाएगी और दूसरी मालवा टीपीएस है, जिसकी राशि 5,794 करोड़ रुपये है, जो 28 दिसंबर, 2014 को शुरु हो चुकी है। यह 15 जुलाई, 2017 तक अपग्रेड हो जाएगी।

– अन्य एमपी जेनको है। कर्जदार–वार वर्गीकरण 5,074 करोड़ रुपये है। यह भी अन्य परियोजनाओं के साथ अपग्रेड हो जाएगी।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– तो, कृपया नाम बताएं? इसका नाम मुझसे चूक गया।

– श्री राजीव शर्मा

– ये कई ऋण हैं परंतु ये मध्य प्रदेश जेनको के हैं।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– ठीक है। मुझे यह पता चल गया है।

– श्री राजीव शर्मा

–एक छत्तीसगढ़ में है। दो परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में और अन्य मध्य प्रदेश में हैं।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– मुझे पता चल गया है। इसलिए, इन तीनों को मिलाकर यह राशि लगभग 18,000 करोड़ रुपये, 17.5 से 18,000 करोड़ रुपये बैठती है।

– श्री राजीव शर्मा

– लगभग 18,000 करोड़ रुपये।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय, मुझे पता चल गया। महोदय, किसी अन्य आरकेएम आदि के लिए हमने, इस तिमाही को लिया है।

– श्री राजीव शर्मा

– हमने 413 करोड़ रुपये की आय राशि को रिवर्स कर दिया है, इसलिए यह मानक परिसंपत्ति है।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– यह अभी भी मानक परिसंपत्ति है। ठीक है। मेरे ख्याल में हमारा एक्सपोजर लगभग 5,000 करोड़ रुपये था।

– श्री नागराजन

– लगभग 5,000 करोड़ रुपये।

– श्री राजीव शर्मा

– लगभग 5,000 करोड़ रुपये, पर इसका धवल पक्ष भी है। पहली यूनिट द्वारा पहले से ही उत्तर प्रदेश को बिजली आपूर्ति की जा रही है और उनके साथ बिजली क्रय करार हुआ है और दूसरी यूनिट जल्द ही शुरु हो जाएगी और इससे बिजली उत्पादन शुरु हो जाएगा।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय। इसके अलावा, मेरा मतलब अन्य एक्सपोजर से है अर्थात निजी क्षेत्र एक्सपोजर के बारे में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अभी कितनी स्लिप है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी कितना स्लिप हो सकता है। मेरा मतलब है कि गत वर्षों में संवितरण के आंकड़ों से हमें पता चलता है कि हमारा एक्सपोजर केएसके के साथ रहा है। इसलिए, मैं इस बारे में कुछ सूचना लेना चाहता था।

– श्री राजीव शर्मा

– भविष्य के बारे में कुछ कहना मुशिकल है, पर निजी क्षेत्र के लिए जो भी प्रावधान किए जाने थे, उन्हें शत–प्रतिशत पूरा कर दिया है। ये सभी निधिकरण बैंकों के सहयोग से हो रहा है, इसलिए हम अन्य संघ साझेदारों के अनुसार आरबीआई मानकों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। इस संबंध में, मैं इतना ही कह सकता हूं कि निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए भी अब स्थितियां सुधर और बेहतर हो रहीं हैं। उत्तर प्रदेश को अधिक बिजली चाहिए, इसलिए अब कई बिजली क्रय करार किए जा रहे हैं। इसलिए, अब से स्थितियां और बेहतर होती जाएंगी। कैबिनेट ने हाल ही में कोयला लिंकेज नीति का अनुमोदन कर दिया है, और राज्य वितरण कंपनियां बोली लगाएंगी और जिस किसी कंपनी ने भी बिजली क्रय करार किया होगा, उसे कोयला लिंकेज मिल जाएगा। इनका बंटवारा, जिला वितरण कंपनियों द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की नीति अभी बनाई गई है, पहले नहीं थी। इसलिए, स्थितियां सुव्यवस्थित हो गई हैं और उनमें सुधार हो रहा है।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– ठीक कहा। महोदय, मेरी ओर से दो बातें। एक तो 35,995 के बारे में हो जो स्लाइड–2 पर दिया गया है जो पुनर्गठन के लिए मानक परिसंपत्ति है। वास्तव में अभी निजी क्षेत्र में का है जो पुनर्गठन बही में शामिल हो सकता है या उससे बाहर हो सकता है। मेरा मतलब है कि यदि कोई जानना चाहे तो इसकी संख्या क्या होगी?

– श्री राजीव शर्मा

– सभी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, इनमें से एक नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जो रेलवे और एनटीपीसी के बीच संयुक्त उद्यम है। इसकी राशि 2,976 करोड़ रुपये है और यह 2017–18 में चालू होगी। दूसरी, 2 X 500 मेगावाट वाला बिहार जेनको का बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी राशि 2,522 करोड़ रुपये है। यह भी 2017–18 में चालू होगी। अन्य परियोजना सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यह राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमि. की सरकारी बिजली उत्पादन परियोजना है, जिसकी राशि 3,798 करोड़ रुपये है। यह भी 2017–18 में चालू होगी।

– और एक अन्य 211 करोड़ रुपये का रामगढ़ गैस प्रोजेक्ट है, जो इसी वर्ष चालू हो जाएगा। केरल राज्य विद्युत बोर्ड की 2 x 30 मेगावाट वाली 191 करोड़ रुपये की पल्लीवसल विस्तार योजना है, जो इसी वर्ष चालू होगी। तमिलनाडु जेनको 1,467 करोड़ की अन्य परियोजना 1 x 600 मेगावाट की एन्नोर विस्तार टीपीएस है। यह भी इसी साल चालू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी शत–प्रतिशत सरकारी परियोजनाएं हैं। इसलिए, इसमें से 58 प्रतिशत या 20,890 करोड़ पहले ही कमिशनिंग हो चुके हैं और वित्त वर्ष 2017–18 में रिवर्स हो जाएंगे।

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– सही कहा, मुझे पता चल गया है। महोदय, मेरी ओर से एक अंतिम प्रश्न। एक बात देखने में आई है कि इस वर्ष इन संवितरणों का काफी बड़ा हिस्सा अल्पावधि ऋणों, खरीदारों के लाइन ऑफ क्रेडिट से आया है। महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं से हमें कितना लाभ होगा? धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– मोटे तौर पर 10.5 प्रतिशत

– श्री धवल गादा – सुंदरम म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय। समस्त सूचनाएं देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– आपका भी बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगले प्रश्न से पहले, सभी प्रतिभागियों को यह स्मरण करा देना चाहता हूं कि हर प्रतिभागी केवल 2 प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न एचडीएफसी म्युचुअल फंड के श्री आनंद लड्डा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– महोदय, क्या आप बता पाएंगे कि इस तिमाही में कुल ब्याज रिवर्सल कितना है?

– श्री राजीव शर्मा

– 940 करोड़ रुपये।

– श्री आनंद लड्डा –एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक। इसमें से इस तिमाही में 527 करोड़ रुपये एनपीए के हैं, और 413 करोड़ रुपये किस लिए हैं?

– श्री राजीव शर्मा

– आरकेएम।

– श्री आनंद लड्डा –एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है। महोदय आपने बताया कि इस तिमाही में भी कुछ निजी क्षेत्र खाते एनपीए में आ गए हैं।

– श्री राजीव शर्मा

– इंड भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड ।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है। महोदय, इस पर कितना एक्सपोजर था?

– श्री राजीव शर्मा

– 442 करोड़ रुपये ।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– और महोदय, इस पर कितना ब्याज रिवर्सल होगा और हो सकता है?

– श्री नागराजन

– लगभग 30 करोड़ रुपये की आय रिवर्स की गई थी।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– महोदय, तीसरी–चौथी तिमाही से तिमाही आधार पर तुलना करने पर देखा जाए तो ब्याज आय लगभग 1,400 करोड़ रुपये कम हो गई है। इसमें से 900 या 950 करोड़ रुपये ब्याज रिवर्सल के कारण हैं। महोदय, क्या यह बकाया उधारी दर में कमी के कारण हुआ है या किसी अन्य कारण से?

– श्री नागराजन

– क्या आप संख्या दोबारा बताएंगे?

– श्री आनंद लड्डा –एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– यदि आप चौथी तिमाही से तीसरी तिमाही की तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्याज आय 1,400 करोड़ रुपये कम हो गई है। इसलिए, तीसरी तिमाही में ब्याज आय 6,900 करोड़ रुपये और चौथी तिमाही में 5,500 करोड़ रुपये थी। क्रमवार घटे 1,400 करोड़ रुपये में से, 950 करोड़ रुपये ब्याज रिवर्सल से संबंधित हैं और यह अनुमान लगाना उचित होगा कि बाकी कमी उधार आय के कारण हुई।

– श्री नागराजन

– श्री आनंद, हम खातों की जांच करने के बाद आपको बता पाएंगे।

– श्री आनंद लड्डा –एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय। महोदय, आपने बताया कि इस तिमाही में निजी क्षेत्र में भी कुछ राशि को अपग्रेड किया गया है। महोदय, यह राशि कितनी होगी?

– श्री राजीव शर्मा

– लगभग 920 करोड़ रुपये के चालू ऋण खातों को अपग्रेड कर मानक बना दिया गया है। एक 560 करोड़ रुपये का अलखनंदा हाइड्रो, महाराष्ट्र में 230 करोड़ रुपये की पवन परियोजना आरएस इंडिया, 97 करोड़ रुपये का सिक्किम पावर प्रोजेक्ट, और अन्य गुजरात की 32 करोड़ रुपये की एस्टन फील्ड सौर ऊर्जा परियोजना है।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है। ये सभी इस तिमाही में अपग्रेड हो गई हैं।

– श्री राजीव शर्मा

– जी हां ।

– श्री नागराजन

– कुछ पूर्ववर्ती तिमाही में थी और कुछ चालू तिमाही में।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– महोदय, क्या हमने आरकेएम पर एक तिमाही या छह महीनों के लिए ब्याज को रिवर्स कर दिया है?

– श्री नागराजन

– नहीं। हमने पूरे वर्ष के लिए 416 करोड़ रुपये रिवर्स कर दिए हैं।

– श्री राजीव शर्मा

– 413 करोड़ रुपये।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय। धन्यवाद। मुझे इतने ही प्रश्न पूछने थे।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत – बहुत धन्यवाद।

– श्री नागराजन

– श्री आनंद, हम 1400 करोड़ रुपये के बारे में पुनः बात करेंगे।

– श्री आनंद लड्डा – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– ठीक है, महोदय।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न एडिलवाइस सिक्योरिटीज के श्री कुणाल शाह का है। कृपया प्रश्न पूछें।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– महोदय, ब्याज आय रिवर्सल के बारे में ही मेरा प्रश्न है। महोदय, बकाया जीएनपीए के बारे में आपकी क्या राय है, जो 30,000 करोड़ रुपये है? क्या 23,000 करोड़ रुपये में से 527 करोड़ रुपये पूरे वर्ष के लिए है?

– श्री नागराजन

– ऐसा नहीं है। जैसा हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पहले आपको स्पष्ट किया है कि हमने उन्हें देय राशि का शत प्रतिशत अधिग्रहण किया है। हमारे पास तिमाही अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर और जनवरी के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची है। इस प्रकार, अंतिम भुगतान 15 जनवरी को किया गया था। इसलिए, हमने 14 जनवरी तक ब्याज अर्जित किया है, और15 जनवरी से 31 जनवरी तक, आम तौर पर यह मानक परिसंपत्ति होने पर, हम प्रोद्भूत आधार पर उपलब्ध करवाएंगे। इन खातों के एनपीए बन जाने के तथ्य के कारण, हमने नकदी आधार पर व्यवस्था की है। इसलिए, जो कुछ भी आय 14 जनवरी से 31 मार्च तक हुई है, हमने उसके लिए कोई प्रावधान न करके इसे रिवर्स कर दिया है। इसलिए, जैसे ही इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा तो संबंधित तिमाही में लाभ मिलना शुरु हो जाएगा जैसा हमारे सीएमडी ने कहा है कि कुछ खाते दूसरी और तीसरी तिमाही में अपग्रेड होंगे। और तब, ये रोकड़ लेखाकरण होगा, जिसमें 75 दिनों का प्रोद्भूत

लेखाकरण होगा। यह लाभ हमें दूसरी और तीसरी तिमाही में मिलेगा जब अपग्रेडेशन होगा।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– जी। परंतु, ब्याज आय रिवर्सल पर प्रभाव कितना है क्योंकि वसूली दर 100 प्रतिशत है। इसलिए, जब मैं 30,000 करोड़ रुपये या 23,000 करोड़ रुपये उत्तरोत्तर वृद्धि की पूरे वित्त वर्ष 2018 के लिए बात करता हूं, तो उसमें कोई बड़ा रिवर्सल नहीं होना चाहिए।

– श्री नागराजन

– जी, 100 प्रतिशत होने वाला है, जैसा आप जानते हैं।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– जी, 100 प्रतिशत कब?

– श्री नागराजन

– रोकड़ लेखाकरण 15 अप्रैल तक होगा। इसलिए, अपग्रेडेशन होने पर, हमें इस वित्त वर्ष में 75 दिनों का प्रत्यक्ष लाभ होगा, जो हमने पूर्ववर्ती वर्ष में खो दिया था।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– जी, ऐसा कोई भी खाता नहीं है, जिसमें हमें रोकड़ प्राप्त न हो रहा हो। यदि आप इस पर नजरें डालें, तो प्रोद्भूत से रोकड़ में शिफ्ट होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता, खाते में कोई अंतर पैदा नहीं होता।

– श्री नागराजन

– इस वर्ष हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा परंतु, अपग्रेडेशन होने पर, हमें इस वित्त वर्ष में 75 दिनों का लाभ होगा। जो कुछ भी हमें वित्त वर्ष 2017 में हानि हुई, उसका लाभ हमें वित्त वर्ष 2018 में अपग्रेड होने पर मिलेगा क्योंकि तब यह प्रोद्भूत लेखाकरण में तब्दील हो जाएगा।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। पुनर्गठित के संबंध में आपने बताया है कि 36,000 करोड़ में से 31 प्रतिशत 2018 में कमिशनिंग हो जाएगा। इसलिए, मोटे तौर पर 45–50 प्रतिशत वित्त वर्ष 2020 में पूरा हो जाएगा। पंरतु, 2016–17 के बकाया के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर कितनी राशि खर्च हुई?

– श्री राजीव शर्मा

– मैं इसका विवरण देता हूं। 58 प्रतिशत या मोटे तौर पर 20,890 करोड़ पहले ही कमिशनिंग हो चुकें हैं और वित्त वर्ष 2018–19 में रिवर्स हो जाएगा।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। यह 58 प्रतिशत है।

– श्री राजीव शर्मा

– जी महोदय, 31 प्रतिशत या 11,165 करोड़ रुपये 2017–18 के दौरान कमिशनिंग होगा। 10 प्रतिशत या 3,670 करोड़ रुपये 2018–19 में कमिशनिंग होगा।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। तो, इसके बड़ा हिस्सा पूरा होगा।

– श्री राजीव शर्मा

– जी।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– जी, उत्तरोत्तर उधारी आय के संबंध में पूछना चाहता हूं कि चौथी तिमाही में किए गए संवितरणों पर अब तक उधारी लाभ कितना है?

– श्री नागराजन

– ज्यादा से ज्यादा यह 10 से 10.71 प्रतिशत होगा।

– श्री कुणाल शाह –एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– 10 या 10.5 प्रतिशत। बही आय लगभग 11.4 प्रतिशत है।

– श्री नागराजन

– अब जितनी भी आय है वो पूरी बही के लिए है।

–श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– जी, पूरी बही के लिए।

– श्री नागराजन

–देखें, तिमाही की संख्या 10.80 के लगभग है।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। और अंत में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में, यह बताया गया है कि हमारे पास 12.5 प्रतिशत जीएनपीए है और रिपोर्ट के आधार पर यह 22.5 प्रतिशत हो सकता है। क्या तिमाही के दौरान दर्ज तंगी के कारण क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड में कोई जोखिम है या हमारे लिए उधारी लागत बढ़ रही है।

– श्री नागराजन

– यह बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन सबका प्रावधान लेखा बहियों में किया जाता है और इसलिए, हम वसूली के महत्त्व पर जोर दे रहे हैं। इसी कारण से हम सभी राज्य स्तरीय उत्पादन कंपनियों में 100 प्रतिशत वसूली कर रहे हैं। स्लाइड में हमने लगभग 97 प्रतिशत समग्र वसूली दर का उल्लेख किया है। उन्हें एक बात चूक के बारे में करनी है। क्या कंपनी ने पुनर्भुगतान बाध्यता में कोई चूक की है। स्पष्ट रूप से बता देने के कारण हम वसूली पर शत प्रतिशत जोर दे रहे हैं कि हम राज्य क्षेत्र के कर्जदारों से 100 प्रतिशत और अन्यों से 97 प्रतिशत वसूली कर पा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि इसका कोई असर होगा।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है।

– श्री राजीव शर्मा

– हमें भविष्य में भी कोई तंगी नजर नहीं आती क्योंकि ये शत–प्रतिशत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं। पूरे भारत में हमारा मूलधन और ब्याज नियमित रूप से अदा किया जा रहा है। आज की तारीख तक, राज्य स्तरीय क्षेत्र में कोई भी एनपीए नहीं है।

– श्री नागराजन

– श्री कुणाल, एक अन्य मुद्दा है। एनपीए वाली एक परियोजना 2012 से मूलधन दे रही है और ब्याज भी अदा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के कर्जदार होने की स्थिति में ऐसा कभी नहीं होता। यह मामला तमिलनाडु जेनको का है। वह 2012 से मूलधन एवं ब्याज अदा कर रहे हैं। परियोजना आज की तारीख तक चालू नहीं हुई है। इसलिए, हमने तुलन पत्र में यह बात बता दी थी। उनके साथ एसक्रो सुविधा के साथ निधिकरण हो रहा है।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। यह वर्तमान में एनपीएल में है।

– श्री राजीव शर्मा

– जी।

– श्री नागराजन

– जी। ऐसा आरबीआई मानकों के कारण है।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– हम कब विद्युत मंत्रालय के पास गए थे। आरबीआई ने यह कब जारी किया। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी?

– श्री नागराजन

– इसीलिए, हमें हमेशा नुक्सान हुआ। इसी कारण हमने इसका प्रावधान किया है।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

– ठीक है। महोदय, ऐसा नहीं है।

– श्री नागराजन

– आरबीआई की दलील है कि एक विनियामक के रूप में वो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपबंध में अंतर नहीं करता। उनका कहना है हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए, परंतु पीएफसी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसमें एकल क्षेत्र निधिकरण है और सभी बिजली उत्पादन कंपनियां उसी कंपनी में हैं। उनके पास हर परियोजना के प्रयोजन से भिन्न एसपीवी नहीं है। इसी कारण पीएफसी के लिए ऐसी विचित्र स्थिति पैदा हुई, जिसके कारण हमने आरबीआई से कुछ छूट देने के लिए अनुरोध किया है, पर उनका कहना है कि आपको मानकों का पालन करना ही पड़ेगा भले ही आप सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की।

– श्री कुणाल शाह – एडिलवाइस सिक्योरिटीज

–ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बहुत धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत बहुत धन्यवाद।

– संचालक

–धन्यवाद। अगला प्रश्न मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस के मुदित पेनुली (Painuly) की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा ही बुनियादी है। वर्तमान में आपके द्वारा पालन किए जा रहे आरबीआई मानकों और आपके द्वारा पालन किए गए पुराने मानकों में क्या अंतर है? अब आपको इन्हें एनपीएल के रूप में डाउनग्रेड करने के लिए क्यों कहा गया है?

– श्री नागराजन

– देखिए, एमओपी अनुमोदन विशेषतः सरकारी क्षेत्र के कर्जदारों की स्थिति में, सीओडी से पूर्व हुए कोई भी पुनर्गठन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है और हमने कोई पुनर्गठित परिसंपत्ति उपलब्ध नहीं करवाई है, न हम प्रदान करते हैं। एकमात्र प्रतिबंध यह है कि हम एक निश्चित अवधि तक पुनर्गठन नहीं कर सकते। हालांकि, वर्ष संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये परियोजनाएं डीसीसीओ कहलाती हैं। वे इसकी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि बुनियादी बात यह है कि हम तुलन पत्र निधिकरण एसक्रो सुविधा के साथ कर रहे हैं। कर्जदार द्वारा मूलधन और ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं होगी। जैसा मैंने अभी बताया है कि इनमें से एक परियोजना तमिलनाडु जेनको चीनी मिल है। वहां, आज की तारीख तक परियोजना शुरु नहीं हुई है, पर तमिलनाडु जेनको द्वारा अपने देयों के रूप में मूलधन और ब्याज का भुगतान अक्तूबर 2012 से किया जा रहा है। हमें यह बात पूरी तरह मालूम है कि वो इसमें चूक नहीं करेंगे इसलिए, सरकारी क्षेत्र के कर्जदारों के प्रति हमारा रवैया थोड़ा नम्र है। परंतु, आरबीआई ने हमें मानकों का पालन करने के लिए कहा है चाहे सरकारी कंपनी हो या निजी क्षेत्र की। इसलिए, 2 + 1 + 1 का मानक लागू है। आप यह शर्त लगाने के लिए कह रहे हो कि तमिलनाडु जेनको जैसे मामलों में इसे एनपीए कर देना चाहिए क्योंकि इनके शुरु होने में विलंब हो रहा है। दूसरा, हमने सरकारी कर्जदारों की स्थिति में पुनर्गठन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है जबकि, निजी क्षेत्र के लिए हमने 4.25 प्रतिशत की व्यवस्था की हुई है। यही आरबीआई के मानकों और हमारे मानकों में बड़ा अंतर है।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– तो आपका कहना है कि निजी क्षेत्र के मानकों में आप इसे एनपीएल के रूप में वर्गीकृत करने के कारण 4 वर्ष तक पुनर्गठित कर सकते हैं। परंतु, सरकारी कर्जदारों के लिए 4 साल की समय सीमा नहीं है।

– श्री नागराजन

– जी।

– श्री राजीव शर्मा

– जी।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– यदि आपको इससे वापस भुगतान आना शुरु नहीं हो जाता तो, आपको इसे एनपीएल के रूप में अब तक मान्यता देनी पड़ेगी। पुनर्गठन के मानक क्या हैं? यह मानक से पुनर्गठित कैसे हो गया?

– श्री नागराजन

– बुनियादी तौर पर आरबीआई के मानकों के अनुसार यह 2 + 1 + 1 ही है, यदि यह दो वर्ष के लिए है। यदि आप परियोजना लागत को 10 प्रतिशत बढ़ाए बिना पुनर्गठन करते हो तो यह पुनर्गठित परिसंपत्ति नहीं हो सकती। यदि आप 10 प्रतिशत लागत बढ़ाते हुए दो वर्ष के अंदर पुनर्गठन करते हो तो इसे पुनर्गठित लेन–देन माना जाता है। कर्जदार के नियंत्रण के बाहर 2 से 3 वर्ष बाद भी यह पनुर्गठित परिसंपत्ति होती है और कानूनी मुद्दा हो जाने के कारण यह अवधि 4 वर्ष हो जाने पर भी यह पुनर्गठित परिसंपत्ति होगी। इसी कारण से यह सभी पुनर्गठित परिसंपत्ति के अंतर्गत आती हैं।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– लेकिन इन्हें पहले राज्य के साथ पुनर्गठित के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

– श्री नागराजन

– यह बात मैंने पहले आपको बता दी थी।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– जी। आपने बताई थी। आपने न केवल इसे स्वीकार कर लिया है, बल्कि इसे पुनर्गठित के रूप में मान्यता दे दी है। महोदय, अन्य बात है, आपने 10 प्रतिशत का प्रावधान किया है। मान लिया इस वर्ष उनमें से कुछ अपग्रेड नहीं हो पाते तो, आपको और वृद्धि करनी पड़ेगी या शायद अगले वर्ष उसके बाद प्रावधान करने पड़ेगा।

– श्री नागराजन

– देखिए, सबसे पहले तो पुनर्गठित परिसंपत्ति का प्रावधान बहुत ज्यादा है क्योंकि यह लगभग 1,400 करोड़ रुपये है। वास्तव में यह इस वर्ष या अगले वर्ष शुरु हो रही हैं। हमें केवल 0.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान करने की जरुरत है क्योंकि आरबीआई ने आदेश दिया है कि मार्च, 2018 तक आपको आरबीआई मानक लाने होंगे। इसलिए, हम उस पर केवल 0.75 प्रतिशत अतिरिक्त ही देंगे। जैसे सीएमडी ने कहा है कि 15,883 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां की कमिशनिंग की गई है और उनसे लाभ भी मिल रहा है। इसके डाउनग्रेड होने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि अप्रैल तक इनसे सभी देय राशि प्राप्त हो चुकी है, हमें केवल जुलाई और अक्तूबर तक इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश में

मालवा जुलाई में शुरु हो जाने पर अपग्रेड हो जाएगी और मारवा अक्तूबर में अपग्रेड हो जाएगी।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– जी, मुझे समझ आ गया है। दूसरी बात, क्या कोई अन्य राज्य परियोजना भी है, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की जाए और जिसे आपने अभी तक वर्गीकृत नहीं किया है, जिसे आप नई उधारी से जानते हो। पिछले कुछ वर्षों में, आपके विचार से कौन सी परियोजना एनपीएल में आ गई है।

– श्री नागराजन

– यह सभी 01.04.2015 से पहले दिया गया है। इसके बाद, हम पुनर्गठन कमिशनिंग आदि के लिए आरबीआई के मानकों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए ये सभी ऋण और अन्य 31 मार्च, 2015 से पहले दिए गए हैं।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– नहीं महोदय। मेरे कहने का मतलब यह है कि नई उधारी से आपको क्या कोई तंगी होगी?

– श्री नागराजन

– वित्त वर्ष 2016–17 में दी गई नई उधारी वाली परियोजनाएं 2020–21 में ही चालू होंगी। हमने हाल के समय में केवल सौर उधारी ही दी है। ऐसा पिछले 3–4 वर्ष से हो रहा है।

– श्री मुदित पेनुली – मैक्स लाइफ इन्श्योरेंस

– ठीक है। महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के श्री दिगांत हरिया (Digant Haria) की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

–श्री दिगांत हरिया – एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग

–महोदय, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि हमें यूडीएवाई से कितने पूर्व–भुगतान होने की उम्मीद है क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र बहुत देरी से इसमें शामिल हुए हैं। इसलिए, इसमें कितना पूर्व–भुगतान होगा?

– श्री राजीव शर्मा

– उन्हें पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

– श्री दिगांत हरिया – एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग

– हम वित्त वर्ष 2018 में किसी पूर्व–भुगतान की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।

– श्री नागराजन

– यदि पश्चिम बंगाल यूडीएवाई में शामिल हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है तो वो खुद पूर्व–विक्रय कर सकता है।

– श्री दिगांत हरिया – एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग

– ठीक है महोदय। वित्त वर्ष 2018 में वृद्धि के लिए, क्या हमारे पूर्व निर्धारित दिशानिर्देश हैं, जिससे हमारे संवितरण बढेंगे। यदि हां, तो कितने बढेंगे और ये कहां से आऐंगे।

– श्री राजीव शर्मा

– हमारे संवितरण 35 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

– श्री दिगांत हरिया – एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग

– महोदय, यह कितने वर्ष में हो पाएगा।

– श्री राजीव शर्मा

– ऐसी भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है, परंतु निश्चित रूप से यह संख्या अच्छी होगी।

– श्री दिगांत हरिया – एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग

– ठीक है। धन्यवाद महोदय।

– श्री राजीव शर्मा

– धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न रिलायंस म्युचुअल फंड के श्री श्रेय लूनकर की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– नमस्ते महोदय। आपका धन्यवाद। महोदय मुझे 2–3 प्रश्न पूछने हैं। पहला, क्या आरबीआई से हुए पत्राचार में कर्जदार–वार वर्गीकरण बनाम सुविधावार वर्गीकरण पर कोई चर्चा हुई? इस बारे में आपके क्या विचार हैं?

– श्री नागराजन

– परियोजना चालू होने में विलंब होने के अलावा हमें कर्जदार–वार वर्गीकरण करना होगा। परियोजना की शुरुआत में विलंब होने पर, हमें परियोजना के आधार पर वर्गीकरण करना होगा। इसके अलावा, सारे वर्गीकरण हमें कर्जदार–वार करने होंगे। इसी कारण, हमने उन दिनों मध्य प्रदेश के मामले में परियोजना की शुरुआत होने के बाद ऋण का पुनर्गठन किया है। हमने सरकारी क्षेत्र के लिए आरबीआई मानकों की मात्रा निर्धारित नहीं की है। इसलिए हमने पुनर्गठन कर दिया है। इसी कारण पूरे मध्य प्रदेश के ऋण को हमने लगभग 11,000 करोड़ रुपये एनपीए में डाउनग्रेड कर दिया है। डीसीसीओ समस्य होने पर, यह परियोजना विशेष की समस्या होगी। डीसीसीओ से भिन्न होने पर हमें पूरी परियोजना को डाउनग्रेड करना होगा जैसा आरबीआई के दिशानिर्देश हैं।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– तब तो यह कट ऑफ के 2–3 वर्षों, ऋण बुक अवधि के बाद पूरी ऋण बुक बही पर लागू होगा।

– श्री नागराजन

– नहीं यह बकाया ऋण बुक होगी। कोई कट ऑफ नहीं होगी।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– ठीक है। यदि मैं सही समझ पा रहा हूं तो अपग्रेड की शर्तों में दिया गया है कि पहले से एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों पर कोई देय पहले से बकाया नहीं होना चाहिए।

– श्री नागराजन

– सीएमडी ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक, मेघालय के सिवाए यह प्रक्रियाधीन वसूली है, जो हमें लगभग 4 करोड़ करनी है और मालवा और मारवा ने 31 मार्च तक अपने देयों का भुगतान कर दिया है और उन्हें केवल अप्रैल, जून और जुलाई के लिए भुगतान करना है। वे देश में सबसे बेहतर कर्जदार हैं, इसलिए हमें इन दो कर्जदारों से कोई समस्या नहीं होने वाली है।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– तो एनपीए के लिए अपग्रेड करने के लिए कौन सी एकमात्र शर्त है?

– श्री नागराजन

– पहली पुनर्भुगतान तारीख से 1 वर्ष। इसलिए, मालवा के लिए पहला पुनर्भुगतान जुलाई, 2016 में हुआ इसी तरह इसकी दूसरी किस्त जुलाई 2017 में अदा की जाएगी। मारवा की स्थिति में ये अक्तूबर 2016 और अक्तूबर 2017 होगी। अतः केवल दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही हैं, जिसके लिए दोनों ऋणों को अपग्रेड किया जाएगा। इसकी राशि लगभग 17,000 करोड़ रुपये है।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– महोदय, क्या आप हमें उन खातों के बारे में कुछ बता पाएंगे, जिन्हें आपने एनपीए बनाया है? क्या यह बैंकिंग सिस्टम के लिए भी एनपीए होगा?

– श्री नागराजन

– जी, ये सभी हमारे द्वारा एकल उधारी हैं। पीएफसी द्वारा पूर्णतः निधिबद्ध या आरईसी द्वारा पूर्णतः निधिबद्ध के सिवाए किसी व्यवस्था की स्थिति में संयुक्त उधारी का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। जैसाकि आप जानते हैं कि हमने आरबीआई से छूट ले रखी है कि हम मार्च, 2022 तक एकल पार्टी एक्पोजर मानकों का पालन न करें। इसलिए परियोजना की लागत के आधार पर हम उनकी इच्छा के अनुसार निधि प्रदान करते हैं। इसी कारण, इन परियोजनाओं में कोई उधारदाता नहीं होगा।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– सही कहा। महोदय, आपके विचार से आरबीआई द्वारा अचानक हमें बैंकिंग मानकों के साथ मिलाने की बात के पीछे क्या कारण है क्योंकि इस क्षेत्र को अभी भी निधिकरण मिलना संभव प्रतीत नहीं होता।

– श्री नागराजन

– रिलायंस म्युचुअल फंड एक बड़ा संगठन है और खुद यह प्रश्न पूछ सकता है। फिर भी, मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई का कहना है कि हम विनियमित तरीके से राज्य सरकार को अलग से छूट नहीं दे सकते। यह विनियमन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए है। इसलिए उनका कहना है कि हम आपको छूट नहीं दे सकते। यह उम्मीद की जाती है कि दी गई छूट परियोजना की शुरुआत में होने वाले विलंब के लिए ऋण वार वर्गीकरण के बारे में है।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– ठीक है। महादेय, अंतिम प्रश्न क्या आप हमें विद्युत क्षेत्र में पीपीए रोल आउट के बारे में अपने विचार बताने की कृपा करेंगे? इस क्षेत्र में पीएलएफ के बारे में आप क्या सोचते हैं?

– श्री राजीव शर्मा

– चूंकि अब कैबिनेट ने कोयला लिंकेज नीति को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, इसलिए अब कोयला लिंकेजों की राज्य वितरण कंपनियों द्वारा बोली लगाई जाएगी। जिन परियोजनाओं ने पहले से ही पीपीए कर लिए हैं, उन्हें कोयला लिंकेज भी मिलेगा। फिर भी जिन परियोजनाओं ने पीपीए नहीं किए हैं, उन्हें भी कोयला उपलब्ध करवाने का पूरा मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश की तरह हम 2019 के चुनावों तक सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मेरे विचार से, इसके लिए उत्तर प्रदेश की वितरण कंपनियां और पीपीए करेंगी। इस प्रकार नीतिगत मोर्चे पर भी स्थितियां बेहतर होने लगी हैं।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– परंतु महोदय, आपके विचार से कितने समय में पीपीए रोल आउट शुरु हो जाएगा चाहे यह मध्यम अवधि का हो या दीर्घावधि ?

– श्री राजीव शर्मा

– अब राज्य वितरण कंपनियों को कोयला लिंकेज की पहले ही पेशकश की जा चुकी है और उनसे बोलियां आमंत्रित की जाएगीं, उन्हें ही इस पर कार्य करना है। मेरे विचार से 3–4 महीने लगेंगे, पर इसमें 6 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। यह मेरी उम्मीद है, पर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उसके बाद भी इसमें 3–4 महीने लग सकते हैं।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– ठीक है। महोदय, अंतिम प्रश्न। हम एकल पक्षकार एक्सपोजर से कैसे निपटेंगे। आपको पता है कि वर्ष 2021 आने वाला है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमें कुछ एसईबी पर एक्सपोजर को खुद ही कम करना होगा ?

– श्री राजीव शर्मा

– क्रेडिट परामर्श मानकों के लिए, हमने आरबीआई से 2022 तक के लिए छूट ले रखी है और अपना एक्सपोजर कम करने की कोई जरुरत नहीं है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में कोई एनपीए नहीं है। यह अच्छा, और सुरक्षित कारोबार है। पर इन्हीं दिशानिर्देशों के कारण, हमें इसका प्रावधान करना पड़ा। पर कोई जोखिम नहीं है, आज की तारीख तक उन्होंने कोई चूक नहीं की और मूलधन और ब्याज के भुगतान में कोई चूक होने की संभावना भी नहीं है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों के कारण में इस पर कोई टीका–टिप्पणी नहीं कर सकता, पर निजी क्षेत्र में चूक होने की संभावना के लिए हमें जोखिम के लिए आमतौर पर प्रावधान करना पड़ेगा। सरकारी परियोजनाओं में तुलन पत्र के आधार पर निधिकरण होता है, जैसा कि वित्त निदेशक ने आपको बताया। वर्ष 2012 से अब तक तमिलनाडु सह–उत्पादन परियोजनाएं हमें भुगतान कर रही हैं जबकि परियोजनाएं अभी

शुरु होनी हैं। इसलिए मुझे कोई जोखिम नजर नहीं आता। यह सुविधाजनक स्थिति है। मेरे पोर्टफोलियों में से 80–85 प्रतिशत केवल सरकारी यूटिलिटी हैं। इसलिए, यही मेरी जीविका है, इसलिए हमें अपना एक्सपोजर कम करने की जरुरत नहीं और डिफॉल्ट एसक्रो द्वारा भी यह सुरक्षित है।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– एसपीई में होने पर आपकी एकल पार्टी एक्सपोजर सीमा, विनिर्धारित सीमा से ज्यादा हो जाने पर आपको उस ऋण पर ज्यादा प्रावधान करना होगा।

– श्री नागराजन

–देखिए, हमें कुछ पुनर्समायोजन करना पड़ेगा जैसा कि हमने मालवा के मामले में किया है। हम आरबीआई के मानकों से परिचित नहीं थे, और जो कुछ हमने किया है वो अपने मानकों के अनुसार किया है। हमें आरबीआई के मानकों का पालन करने और अपना कारोबार को इस तरह दोबारा व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है जिससे एकल पार्टी एक्सपोजर प्रभावित न हो।

– श्री श्रेय लूनकर – रिलायंस म्युचुअल फंड

– जी ठीक है। यदि कुछ प्रश्न हुए तो मैं बाद में पूछ लूंगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न सीएलएसए के श्री आदित्य जैन का है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– नमस्कार महोदय। मैं प्रखात कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न एसईबी ऋणों के बारे में है जो मानक ऋण है न कि पुनर्गठित ऋण या एनपीए। उसी एसईबी ऋणों के अंदर क्या आप कुछ ऐसे ऋणों की राशि बताए पाएंगे, जिनका इस्तेमाल शायद निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा या किया जा रहा है और डीसीसीओ 3 या 4 वर्ष से ज्यादा समय ले सकता है। उसके पास यही पुराना विकल्प है।

– श्री नागराजन

– प्रखात। ये सभी स्थितियां 2015 से पहले ही मौजूद थी। मेरे ख्याल से हमने सभी परियोजनाओं को शामिल कर लिया है और हमने मौजूदा और भावी 3–4 परियोजनाओं पर काम किया है। हम यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि क्या यह एनपीए हो जाएगा या नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएंगी।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– मैं पूर्णतः इसकी प्रशंसा करता हूं। परंतु महोदय, कई बार यह मुद्दा पैदा हो जाता है कि ये बहुत भारी भरकम एक्सपोजर हैं और जितनी भी परियोजनाओं के लिए आपने निधिकरण किया है उनमें से एक या दो या तीन में विलंब हो जाने की स्थिति में हर परियोजना का टिकट आकार 4000–5000 करोड़ रुपये हो सकता है। इससे परिवर्धन पक्ष के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। मुझे जानकर खुशी हो रही है कि कई सारे अपग्रेड होने हैं। मैं 2–3 खातों के बारे में जानना चाहता हूं जो उस सीमा को लांघ जाएंगे। हमें वित्त वर्ष 2018–19 में भी काफी बड़े परिवर्धन देखने को मिलेंगे।

– श्री नागराजन

– कुल पोर्टफोलियों में से उत्पादन परियोजनाओं के चालू होने की स्थिति, कुल बकाया राशि 1,83,379 करोड़ है, जिसमें से 1,23,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं जबकि बाकी वित्त वर्ष 2016–17 में 4,069 करोड़, वित्त वर्ष 2017–18 में 26,000 करोड़ और वित्त वर्ष 2018–19 और उससे आगे 15,000 करोड़ की परियोजनाएं चालू होंगी। इन आकंड़ों के आधार पर, लगभग 60,000 करोड़ रुपये में से कॉर्पोरेट ऋण और आरएंडएम होने के कारण 15,000 करोड़ रुपये की कमिशनिंग लागू नहीं होती और ज्यादा बकाया वाले खाते पहले ही एनपीए हो चुके हैं या पुनर्गठित हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। यदि आप इस पर ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो मैं आपकी बात का पुनः उत्तर दूंगा।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– जी। महोदय, दूसरा प्रश्न निजी क्षेत्र की पुनर्गठित बही पर है, जिनसे आप खासे परिचित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भले ही कुछ परियोजनाएं चालू हो जाती हैं या निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है और इनमें से कई के पास पीपीए भी होता है, लेकिन एसईबी बिजली की खरीद नहीं करता और उनमें से कई के पास पीपीए भी नहीं है। क्या पुनर्गठित बही के बारे में कोई सूचना देना संभव होगा कि उनका मूल्य क्या है? यहां मैं केवल निजी क्षेत्र के 19,000 करोड़ के पुनर्गठित ऋण की बात कर रहा हूं। कितनी कंपनियों के पास पीपीए नहीं है और उनके पास पीपीए होने के बाद भी वे 50 प्रतिशत उपयोगिता घटक के नीचे काम कर रही हैं।

– श्री नागराजन

– प्रखात, हम इस पर फिर आऐंगे।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– कोई दिक्कत नहीं महोदय।

– श्री नागराजन

– कोई संदेह होने पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– जी, यदि मुझे कोई जानकारी लेनी होगी तो मैं प्रश्न पूछ लूंगा। क्या आरकेएम पावर ने कोई पीपीए कर रखा है, पर उत्तर प्रदेश उससे नियमित रूप से बिजली नहीं खरीद रहा है।

– श्री राजीव शर्मा

– उत्तर प्रदेश उनसे बिजली खरीद रहा है। पहली यूनिट उत्तर प्रदेश को बिजली की आपूर्ति कर रही है।

–श्री प्रखात – सीएलएसए

– मेरे ख्याल से दूसरी यूनिट जनवरी 2016 में चालू होनी थी और मेरे विचार से यह बड़ी यूनिट भी थी।

– श्री नागराजन

– प्रखात, यह पहले ही चालू हो चुकी है। हमारे सीएमडी ने बताया है कि वो दूसरी यूनिट की अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं।

– श्री राजीव शर्मा

– बाकी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहां तक आरबीआई मानक के कारण प्रभावित हुई अन्य बही के अलावा, बाकी पुनर्गठित बही का संबंध है, यह मोटे तौर पर 19,500 करोड़ रुपये है, 26 प्रतिशत या मोटे तौर पर 5,000 करोड़ रुपये पहले ही कमिशनिंग हो चुका है और 2017–18 में 4,500 करोड़ रुपये और 2018–19 में 500 करोड़ रुपये रिवर्स हो जाएंगे। इस पुनर्गठित बही का 70 प्रतिशत या 13,500 करोड़ रुपये 2017–18 में कमिशनिंग हो जाएंगे।

– श्री प्रखात –सीएलएसए

– जी, क्या उनके पास पीपीए है?

– श्री राजीव शर्मा

– 19,500 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र के हैं।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– मैं इसके बारे में बाद में बात करुंगा। महोदय, लाभ के बारे में, मैं आपके प्रेजेंटेशन की स्लाइड 9 पर नजर डालने पर कुछ अनुपात दिए गए हैं, जो मुख्य सूचक हैं। आरबीआई मानकों के प्रभाव पर विचार किए बिना, जहां निवल ब्याज मार्जिन 3.65 प्रतिशत है, जो रन दरों से काफी कम है, जिस पर आप 4.74 प्रतिशत मार्जिन के साथ तीसरी तिमाही तक काम कर रहे थे। आपके मूल्यांकन के आधार मैं सभी को इसमें से हटाता हूं और इसमें ब्याज रिवर्सल पर मार्जिन पर आरबीआई के सभी प्रभाव का अपवर्जन करता हूं। परंतु, अभी भी ऐसा लगता है कि मार्जिन में लगभग 100 आधार बिंदु पर तिमाही गिरावट आई है।

– श्री नागराजन

– प्रखात, वित्त वर्ष 2017, में यह 4.54 है। उस चौथी तिमाही के लिए 3.65 है। आम तौर पर, वित्त वर्ष के लिए, पूरा वर्ष 4.54 है। आय का रिवर्सल होने के कारण, 2017 की चौथी तिमाही में यह 3.65 है। केवल चौथी तिमाही को न देखकर पूरे वर्ष पर ध्यान दें। यह अभी भी 4.5 है।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– ठीक है। महोदय, लोअर टेबल में उल्लिखित 3.65 और ऊपर उल्लिखित 2.57 के बीच क्या अंतर है? मेरे विचार से, अंकित मूल्य पर सभी समायोजनों के साथ 2.57 दर्ज मार्जिन है जबकि, 3.65 इन एकल समायोजनों के बिना है।

– श्री नागराजन

– कुछ आय रिवर्सल हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– परंतु, मुझे नहीं लगता इसकी पुनर्रावृत्ति होगी। मेरे विचार से यह पहला प्रश्न है, जिसके बारे में शायद आनंद भी कुछ जानना चाहते थे। 500 या 900 करोड़ रुपये और ब्याज आय में 1400 करोड़ रुपये की कमी के बीच आय रिवर्सल कितना है।

– श्री नागराजन

– अब मैं बताता हूं कि 1,400 करोड़ रुपये आय, 900 से 1000 करोड़ रुपये 2 खातों के रिवर्सल सूचक और तत्कालीन परिसंपत्तियों के कारण है। इंड भारत मद्रास के मामले में हमने एनपीए में तब्दील कर दिया है, इसलिए प्रोद्भूत लगभग 30 करोड़ रुपये होगी। मैंने बताया है कि मार्जिनल उधारी दर 10.5 से 10.65 के लगभग है। इसी कारण से आय 1400 से कम हो गई है। मेरे विचार से 6000 से 5500 के बीच हमें 1400 का अंतर देखने को मिलता है।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– इसलिए, यह अनुमान सही प्रतीत होता है कि ब्याज आय में 1400 करोड़ रुपये की कमी में से लगभग 900 करोड़ रुपये रिवर्सल के कारण हैं और 500 करोड़ रुपये एसबीआई द्वारा उधारी दरों में की गई कटौती से मार्जिन में हुई कमी के कारण हैं।

– श्री राजीव शर्मा

– पुनःमूल्यन

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– जी पुनःमूल्यन। इस पर थोड़ी जानकारी और चाहिए। क्या यह कटौती जारी रहेगी क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ एसबीआई जैसे पीएसयू ने यह महसूस किया है कि कुछ अच्छी बिजली उत्पादन कंपनियों में उधारी देने के मौके हैं और मजबूत स्थिति वाली ऋण बही से बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए इससे दबाव बना रहेगा।

– श्री राजीव शर्मा

– हम इस पर कोई भविष्यवाणी/टीका टिप्पणी नहीं कर सकते।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– जी।

– श्री नागराजन

– स्टेट बैंक ने जनवरी के माह में दरों में कटौती की है। मुझे लगता है ऐसा किसी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है। पिछले 3–4 महीनों से किसी भी कर्जदार ने आकर ब्याज दरों में कटौती के लिए नहीं कहा। सीएमडी ने बताया है कि विलय के बाद एसबीआई ब्याज दरों में फिर कटौती कर सकता है। हालांकि, अभी तक किसी ने दरों में कटौती नहीं की और जितने ब्याज की हमें पेशकश की गई है वो हमारे लिए सुविधाजनक है।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– ठीक है। महोदय, अंतिम प्रश्न सौर ऊर्जा स्थलों के बारे में है। क्या आप बता सकते हैं की कुल ऋण राशि कितनी है? इस ऋण में से सौर ऊर्जा की राशि कितनी है और बकाया मंजूरियों के अंदर, कितनी राशि सौर ऊर्जा की होगी? इस पर समग्र दृष्टि डालें। इस क्षेत्र में मूल्य काफी तेजी से गिर रहे हैं। इन परियोजनाओं पर आपके क्या विचार हैं, वे कहां स्थित हैं जिनके लिए आप प्रतिबद्ध हैं? आप जानते हैं कि इन परियोजनाओं के लिए बाजार में अलग मूल्य निर्धारण किया गया है? धन्यवाद।

– श्री नागराजन

– वर्ष 2016–17 में नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत मंजूरी के लिए 6,707 करोड़ रुपये लंबित हैं। वर्ष 2016–17 में हमने 7,164 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है और हमने 2,471 करोड़ रुपये का संवितरण किया है और इसमें से कुल बकाया परिसंपत्ति राशि 5,092 करोड़ रुपये है। संचयी मंजूरी 14,032 करोड़ है, संवितरण 7,325 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा में बकाया परिसंपत्ति लगभग 5,092 करोड़ है और सौर ऊर्जा की औसत उधारी दर 10.5 करोड़ है।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– जी। क्या सौर ऊर्जा के बारे में यही सब है।

– श्री नागराजन

– लगभग 50 प्रतिशत सौर और बकाया अन्य नवीकरणीय ऊर्जा है।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– महोदय, इस बारे में आपकी क्या राय है कि मूल्यों में उतार–चढाव से इन कर्जदारों के रोकड़ प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

– श्री नागराजन

– देखिए, निधिकरण के समय ही हमनें पीपीए ले लिए हैं और तब ही दरें तय कर दी हैं। इस प्रकार, परियोजना संभाव्य होने पर ही हम इसे निधि देते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास एक रुपये के निधिकरण के लिए भी आता है तो हम यह देखते हैं क्या यह संभाव्य है। यह बात सुनिश्चित करने पर ही हम मंजूरी प्रदान करते हैं। यदि वो पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारे पास आते हैं तो संभाव्यता देखने के बाद हम उसे निधि प्रदान करते हैं। ऐसा न होने पर हम इन परियोजनाओं को निधि प्रदान नहीं करते।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– बिल्कुल ठीक।

– श्री गंगोपाध्याय

– जहां तक सौर ऊर्जा की बात है तो यह आपको बता दूं कि बिजली लागत प्रणाली में ऐसा हिस्सा है, जहां परियोजना के अंतर्गत पूर्ण पीपीए होते हैं। सौर ऊर्जा का कोई भी एक मामला नहीं है जहां सौर ऊर्जा व्यापारिक तौर पर बेची जा रही है। इसलिए, पीपीए स्टार्ट–अप है और हम लागत का मूल्यांकन करते हैं। यदि आपकी बाजार पर पूरी नजर है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मूल्य लगभग स्थिर है और इसलिए अगली कुछ तिमाहियों में सौर मूल्यों में काफी कमी होने वाली नहीं है। जहां तक आरबीआई के

2+1+1 मानक का संबंध है तो, इन सभी परियोजनाओं पर एनपीए होने का खतरा नहीं है। इसका कारण है कि इसके चालू होने की अवधि मुश्किल से 9 महीने है और इसलिए, हमें सौर ऊर्जा क्षेत्र में निधिकरण करने में कोई खतरा नहीं लगता।

– श्री प्रखात – सीएलएसए

– धन्यवाद महोदय। इस सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न जेफरीज के श्री नीलांजन कारफा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– धन्यवाद महोदय। पिछले प्रश्न के बारे में आपने बताया था कि 1,83,000 करोड़ की कमिशनिंग में से 1,23,000 करोड़ की कमिशनिंग हो चुकी है। पर 2017–18 और 2019 में कमिशनिंग क्या होगी।

– श्री नागराजन

– वित्त वर्ष 2016–17 में 4,069 करोड़, वित्त वर्ष 2017–18 में 26,000 करोड़ और वित्त वर्ष 2018–19 में 15,000 करोड़ की कमिशनिंग होगी।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– ठीक है। इस 26,000 करोड़ में से कितनी प्रभावित होगी जैसे गत में सीओडी एक्सटेंशन। इसलिए, इसमें जोखिम है।

– श्री नागराजन

– हमारे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। हम बाद में इस पर आएंगे।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 1.8 लाख करोड़ में से कितना केपैक्स ऋण बनाम कार्यशील पूंजी ऋण है?

– श्री नागराजन

– जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं वो उत्पादन ऋण है। यह कोयला, गैस, नवीकरणीय और अन्य हैं। इसलिए, हम इसे एसटीएल के अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– क्या आप इसे कैपेक्स ऋण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं?

– श्री नागराजन

– जी हां।

– श्री राजीव शर्मा

– आवधिक ऋण

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– जी हां। मैंने इसके बारे में सुना है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, जैसा सरकार ने वचन दिया था। क्या कुछ सप्ताह पहले उन्होंने कई पीपीए रद्द कर दिए हैं। क्या आप बता पाएंगे क्या हुआ था?

– श्री राजीव शर्मा

– वे पुरानी बोली वाले पीपीए थे और उन्हें पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान आमंत्रित किया गया था। अब नई सरकार बन गई है इसलिए वो नई बोली आमंत्रित कर सकते हैं क्योंकि इन्हें बिजली की जरुरत है। वर्ष 2019 तक उत्तर प्रदेश सरकार को शहरी और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली सप्लाई करनी है। इसी कारण से उन्हें अतिरिक्त बिजली की जरुरत होगी और बिजली का संयंत्र एक दो दिन में स्थापित नहीं किया जा सकता, इसमें 6 साल लगते हैं।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– सही कहा। यहां आप बताना चाहते हैं...

– श्री राजीव शर्मा

– हमें उम्मीद है कि वे बाजार में नई बोलियां आमंत्रित करेंगे।

– श्री नीलांजन कारफा –जेफरीज

– नई बोलियां पर कम लागत पर।

– श्री राजीव शर्मा

– मैं यह नहीं बता सकता। हम यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वे ऊंची या छोटी बोली होंगी।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– महोदय, इस प्रतिस्पर्धी समय चल रहा है। आप जानते ही हैं पिछले 12 महीनों में एसबीआई से काफी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है।

– श्री राजीव शर्मा

– ज्यादा नहीं। बिल्कुल, पुनर्वित्तीयन के लिए, उन्होंने कुछ सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों से संपर्क किया है और हमें कुछ अपनी दरों में कुछ कमी करनी पड़ी थी। मेरे विचार से, पिछले कुछ महीनों से ऐसा नहीं है। वास्तव में हम सहयोग से काम कर रहे हैं, और कई जगह हमनें एसबीआई के साथ साझेदारी की है।

– श्री गंगोपाध्याय

–बैंक के साथ मिलकर काम करने से, हमें यह उम्मीद है कि बैंक के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा कम होगी क्योंकि आरबीआई के मानक बैंकों पर लागू होंगे। इसलिए, सेक्टरल एक्सपोजर मानक के साथ, वे राज्य क्षेत्र के साथ ज्यादा इच्छुक नहीं होगा।

– श्री राजीव शर्मा

– एसबीआई के सिवाए, किसी भी बैंक ने इस ऊर्जा क्षेत्र में आक्रामक रूख नहीं दिखाया है और इसके पास सहभागिता करने के लिए निवल पूंजी नहीं है।

– श्री गंगोपाध्याय

– वास्तव में वो लघु अवधि के आधार पर उधार नहीं दे रहे हैं और राज्य हमसे दीर्घ अवधि के ऋण लेने के लिए इच्छुक हैं।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– सही कहा, बहुत अच्छा लगा। महोदय, प्रेजेंटेशन में आपने पुनर्समायोजन से संबंधित हानियों को शामिल किए हुए बिना अग्रिमों पर आय 10.39 दिखाई गई है। जब तक अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी, क्या यह मानना उचित होगा कि ऋण पर लाभ लगभग 10.4, 10.5 प्रतिशत होगा। क्या यह सभी मूल्यांकन होगा?

– श्री नागराजन

– इसलिए, मैंने कहा था कि हमने पिछली तिमाही में 10 से 10.5 तिमाही आधार पर किया था। इसलिए हम इन ऋणों पर 10.75 लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले दो महीनों से हमें किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि एसबीआई ने अपनी परिसंपत्तियों के लिए दरें नहीं घटाई हैं, जैसाकि इसने जनवरी में किया था। इसलिए हमें उससे ऐसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। जैसा सीएमडी ने बताया है कि हम एसबीआई, आरईसी और अन्य बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिभागिता करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम नई परियोजनाओं के लिए बोलियां लगा पाएं।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– महोदय, ठीक कहा आपने। पर हम निजी क्षेत्र को 1 से 1.5 प्रतिशत ज्यादा पर उधार दिया करते थे। इसलिए, शायद इसमें काफी कमी देखने को आई है।

– श्री नागराजन

– वहां हमने सौर परियोजनाओं के सिवाए किसी दर में कमी नहीं की है, जहां कर्जदार की रेटिंग के आधार पर हमने दरों को 11 प्रतिशत से घटाकर 9.75 प्रतिशत किया है।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– ठीक है महोदय। अंतिम प्रश्न आंकड़ों के बारे में है। 45,000 करोड की राशि के बारे में विस्तार से बताएं, जिसकी कमिशनिंग होने जा रही है, कितना मेगावाट, गीगावाट क्षमता है और उनमें से कितनों के पास दीर्घकालीन पीपीए हैं और शायद एफएसए?

– श्री नागराजन

– हमने बाकी के 3 वर्षों में कई मेगावाट की परियोजनाओं की शुरुआत की है, 2 वर्ष में लगभग 28,000 मेगावाट, 2017–18 में लगभग 10,711 और 2018–19 में 18,240 मेगावाट। पीपीए, एफएसए का ब्योरा हमारे पास नहीं है। हम इसके बारे में बाद में बताएंगे।

– श्री नीलांजन कारफा – जेफरीज

– ठीक है। धन्यवाद महोदय।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न मार्शल वेड (Wade) के अनिल बैंग की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न प्रसार पक्ष के बारे में है। आपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि पिछले वर्ष ऋण पर प्रसार 3.4 प्रतिशत के लगभग रहा। आपका कहना है कि आप 10.5 पर उधार दे रहे हैं और उधारी की लागत लगभग 7.4 है। क्या यह सही है?

– श्री नागराजन

– जी।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– तो आपका प्रसार अभी भी 3 प्रतिशत से ज्यादा है।

– श्री नागराजन

– जीए 3.13 प्रतिशत।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप उत्तरोत्तर आधार पर इस प्रसार को बनाए रखेंगे।

– श्री नागराजन

– इस प्रश्न का जबाव देना मुश्किल है।

– श्री अनिल बैंग –मार्शल वेड

– नहीं, मेरा मतलब, मेरा मतलब पिछले से...

– श्री नागराजन

– वर्तमान स्तर पर अब इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं है कि लोग 10.5 पर ऋण लेंगे और बांड बाजार में भी उधारी 7.4 से 7.5 होने पर ही हम इस प्रसार को बनाए रखेंगे। यह सब बाजार में यूएस प्रसार देयों पर निर्भर करता है।

– श्री राजीव शर्मा

– हमें 54 ईसी कैपिटल गैन ऋण बांड मिलने हैं। हमने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय में आवेदन किया है। यह अनुरोध वित्त मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है और हमारे अनुरोध को मान लिया जाएगा। यह मिल जाने पर हमारी लागत कम हो जाएगी। इसके होने की संभावना है, हां मैं सौ फीसदी पक्का नहीं कहता कि ये हमें मिल जाएंगे पर इस पर वित्त मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– जी मुझे जानकारी मिल गई। महोदय, उसी स्लाइड यानि स्लाइड नंबर 9 पर एक और बात सुनने में आई है कि मार्जिन और प्रसार के बारे में काफी चर्चा हुई। क्या यह चौथी तिमाही के कारण है, जिसमें आपके ऋण का 88 प्रतिशत निष्पादक ऋण था और उनसे

ब्याज मिल रहा था, जबकि बेस में आप अभी भी 100 पर विचार कर रहे हैं। क्या यह मार्जिन में कमी के पीछे कारण हो सकता है?

– श्री नागराजन

– हमने इस पर कोई शोध नहीं किया है। हम इसकी जांच करके आपको बता पाएंगे। हमने शोध नहीं किया है।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न निजी क्षेत्र के एनपीए और पुनर्गठित के बारे में है। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? विद्यमान पुनर्गठित पूल और एनपीए ऋणों के बारे में आपकी क्या राय है? राज्य स्तरीय ऋणों के बारे में आपने क्या बताया है? धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– आरबीआई मानकों से प्रभावित न होने वाले के अलावा, बकाया पुनर्गठित बही मोटे तौर पर 19,500 करोड़ रुपये है जिसमें से 26 प्रतिशत या 5,000 करोड़ रुपये की पहले ही कमिशनिंग की जा चुकी है, 4,500 करोड़ वित्त वर्ष 2017–18 में और 500 करोड़ वित्त वर्ष 2018–19 में रिवर्स होंगे। इस पुनर्गठित बही के 13,500 करोड़ का 70 प्रतिशत 2017–18 में सीओडी होना है। ये सारी पुनर्गठित बही केवल निजी क्षेत्र में ही है।

– श्री अनिल बैंग – मार्शल वेड

– यह सूचना काफी मददगार है। धन्यवाद महोदय।

– श्री राजीव शर्मा

– आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न एचडीएफसी म्युचुअल फंड के श्री आनंद लाधा की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री आनंद कुमार – एचडीएफसी म्युचुअल फंड

– महोदय, मेरे सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया है।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत बहुत धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न टाटा म्युचुअल फंड के श्री अमिय साठे की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– नमस्ते महोदय। आंकडों संबंधी एक प्रश्न। क्या पुनर्गठित बही में प्रविष्टियों की सूचना देना संभव होगा, जैसे वित्त वर्ष 2017 में शुरुआती एवं परिवर्धन जिसमें से अपग्रेडेशन घटा दिया जाएगा।

– श्री राजीव शर्मा

– हम इस पर बाद में बात करेंगे।

– श्री नागराजन

– जब हम आपके सामने तुलन पत्र रखेंगे, हम यह सूचना उपलब्ध करवा देंगे।

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– ठीक है महोदय। दूसरा प्रश्न संवितरणों के बारे में है। महोदय, संवितरण वाला कॉलम काफी बड़ा हो गया है, ये कौन से संवितरण हैं?

– श्री नागराजन

– देखिए। ये सारे ऋण अल्प अवधि के ऋण हैं, जैसे यूडीएवाई योजना के अनुसार। राज्य वितरण कंपनी पिछले वर्ष के प्राप्यों का 25 प्रतिशत कार्यशील पूंजी के रूप में ले सकती हैं, इसलिए हमने इस अवसर का लाभ उठाकर इसका पिछले वर्ष के प्राप्यों के 25 प्रतिशत तक वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी दी है। कम से कम 2016 तक जो भी प्राप्य थे, हमने वो दिए हैं। इसी कारण से यह कॉलम बड़ा हो गया है। यह यूडीएवाई पर सरकार द्वारा दी गई योजना के अनुसार है। बैंक ये देने का तैयार नहीं हैं इसलिए हमने यह काम कर ऋण दिए हैं।

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– और उस पर उधारी दर कितनी होगी?

– श्री नागराजन

– मैं बताता हूं, यह लगभग 10.25 से 10.50 होगी।

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– ठीक है। उसके आसपास यह 10.25 से 10.50 है।

– श्री नागराजन

– जी ।

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– उंचे स्तर पर कुछ नहीं है?

– श्री नागराजन

– वितरण कंपनियां लाभप्रद हैं, वो इसके लिए भुगतान क्यों करेंगी?

– श्री अमिय साठे – टाटा म्युचुअल फंड

– ठीक है। धन्यवाद महोदय।

– श्री राजीव शर्मा

– धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न इनवेस्को म्युचुअल फंड के श्री देवराज लाहिड़ी की ओर है। कृपया प्रश्न कीजिए। श्री देवराज की ओर से कोई प्रश्न नहीं किया गया है, इसलिए अगला प्रश्न कोटक सिक्योरिटीज के श्री निश्चिंत चवाठे (Chawathe) की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री निश्चिंत चवाठे –कोटक सिक्योरिटीज

– सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत–बहुत धन्यवाद।

–संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न कपूर एंड कंपनी के श्री साकेत कपूर की ओर है। कृपया प्रश्न कीजिए।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– आपके द्वारा की गई विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। मैं एक निवेशक हूं, विश्लेषक नहीं। एक बात समझना चाहता हूं कि ऋण के पुनवर्गीकरण और किसी वास्तविक रोकड़ प्रवाह

के न होने के परिणामस्वरूप लाभ और उसका हर हिस्सा कम हुआ है। क्या इसका समायोजन काफी लंबे समय में होगा।

– श्री नागराजन

– जी, सही कहा आपने।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– महोदय, आपने बताया था कि यदि इन उपबंधों को लागू न किया जाता तो आपका लाभ 6,400 करोड़ होता। इसका मतलब है कि वर्ष के लिए लाभ 6,400 करोड़ बनाम 6184 करोड़ होता।

– श्री नागराजन

– जी।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– ठीक है। अब यूडीएवाई योजना के बारे में बात करते हैं। यह योजना शुरु हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को छोड़कर यह राज्य इस योजना में शामिल हो गए हैं।

– श्री नागराजन

– इन सभी ने अपने ऋणों का पुनर्भुगतान कर दिया है। यूडीएवाई योजना के अंतर्गत भी उन्होंने 31 मार्च से पहले अपने ऋणों का पुनर्भुगतान कर दिया था।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– यह जानना चाहता हूं कि इस योजना को शुरु करने का प्रयोजन क्या था? इस पूरी व्यवस्था को इसके लाभ होगा? हमें इससे क्या लाभ होगा? क्या आप इसके बारे में कुछ अद्यतित जानकारी दे पाएंगे?

– श्री राजीव शर्मा

– जी। 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने इस यूडीएवाई योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 2.33 लाख करोड़ कीमत के बॉड जारी और अभिदत्त किए जा चुके हैं जो कुल बॉडों का 87 प्रतिशत है। यूडीएवाई योजना पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में 97 प्रतिशत फीडर निगरानी कार्य पूर्ण हो चुका है। इन राज्यों में फीडर सेग्ररीगेशन 25 प्रतिशत तक प्राप्त कर लिया गया है और यह कार्य भी मार्च, 2018 तक पूरा हो जाएगा। कम से कम 10 राज्यों ने एसीआर और एआरआर के बीच अंतर को काफी कम कर दिया है। 6 राज्यों ने अपने एटीएंडसी हानियों को कम कर लिया है। इसलिए, यह प्रगति कर रही है।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– महोदय, वास्तविक रोकड़ प्रवाह न होने पर, बोर्ड ने इस तिमाही के लिए लाभांश देने का निर्णय नहीं लिया या पूरा लाभांश इस तिमाही से पहले ही अदा किया जा चुका है?

– श्री नागराजन

– कंपनी अधिनियम के अनुसार लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध है, इसलिए हमने अतिरिक्त लाभांश की घोषणा नहीं की।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– कृपया कंपनी अधिनियम के बारे में विस्तार से बताएं?

– श्री नागराजन

– यह क्या है?

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– हमारे पास वास्तविक रोकड़ प्रवाह है और डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुसार, क्या हमने लाभांश अदा किया है?

– श्री नागराजन

– डीआईपीएएम दिशानिर्देशों में व्यवस्था है कि कुल मूल्य को 5 प्रतिशत या पीएटी का 30 प्रतिशत या कंपनी अधिनियम के विनियमों की शर्तों के कारण, हमें इक्विटी और फीस रिजर्व के 10 प्रतिशत के अधीन रहते हुए तीन वर्ष के औसत लाभांश को ध्यान में रखना होगा। इसमें 200 करोड़ की कमी हो रही है। हमने जरुरत से ज्यादा लाभांश अदा कर दिया है, जो हमें अदा नहीं करना चाहिए था। इसी कारण हमने लाभांश का भुगतान नहीं किया।

–श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– ठीक है महोदय। महोदय, मेरे प्रश्न का अंतिम भाग। हमारे कुल ऋणों में से कितना हिस्सा नवीकरणीय और कितना गैर–नवीकरणीय ऊर्जा के निमित्त खर्च होता है?

– श्री नागराजन

– कुल बकाया परिसंपत्ति, नवीकरणीय कुल मंजूरी संचयी 14,000 करोड़, संचयी संवितरण 7,235 करोड़ हैं। इस वर्ष में, हमने 7,164 करोड़ की मंजूरी, 2,471 करोड़ का संवितरण किया है। ऋण परिसंपत्तियों के रूप में बकाया 5,092 करोड़ है, औसत उधारी दर 10.5 करोड़ है।

– श्री साकेत कपूर –कपूर एंड कंपनी

– धन्यवाद।

– संचालक

– श्री कपूर। मैं हस्तक्षेप करने के लिए माफी मांगता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अपने प्रश्न पर दोबारा आएं।

– श्री साकेत कपूर – कपूर एंड कंपनी

– जी महोदया, धन्यवाद।

– संचालक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड के कैतल शाह की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछें।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड

– इस प्रश्न को पूछने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपकी ओर से जानना चाहता हूं कि संघ की उधारी कितनी होती है और कितनी अलग उधारी है?

– श्री नागराजन

– सरकारी क्षेत्र के कर्जदारों की स्थिति में, यह अलग है। केवल निजी क्षेत्र के कर्जदारों की स्थिति में निजी क्षेत्र का 80 प्रतिशत संघ की उधारी में बुक होगा।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड

– निजी क्षेत्र का 80 प्रतिशत।

– श्री नागराजन

– जी। एकल आधार पर ऐसा किया जाएगा यदि राशि बहुत कम हो। यदि आप सही आंकड़े जानना चाहता हो तो हम आपको बाद में बताएंगे।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड

– निश्चित रूप से मैं ऐसा करुंगा। इस तिमाही में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित परिसंपत्तियों के अर्थ में, क्या आप इन सब में ब्याज आय को अभी भी मान्यता दी जा रही है और क्या उसमें से कुछ आगामी वर्ष में एनपीए हो जाएंगी।

– श्री नागराजन

– एक बार एनपीए श्रेणी में आ जाने पर, हम आय को संशोधित करेंगे।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड

– माफी।

– श्री नागराजन

– हमें इन परियोजनाओं में कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने देयों का भुगतान कर रही है। मूलधन की तरह ब्याज भी ज्यादातर परियोजना द्वारा भुगतान किया जा रहा है।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड.

– सही है। इसलिए, आपको पहले से ही आय नकद प्राप्त हो रही है, यह प्रोदभूत नहीं है। मोटे तौर पर, आपका क्या कहना है?

– श्री नागराजन

– नहीं। प्रोद्भूत आधार पर ही हम प्राप्त कर रहें हैं। पर वस्तुस्थिति यह है कि इस परियोजना में कोई दिक्कत नहीं है। इस निमित्त रोकड़ प्रवाह की समस्या नहीं है क्योंकि कमिशनिंग अभी नहीं हो पाई है। वो बकाया शीट निधिकरण के कारण मूलधन और ब्याज अदा किया जा रहा है। एक बार ये एनपीए में शिफ्ट हो जाने पर, किसी तिमाही विशेष के लिए आय का रिवर्स कर देंगे यदि यह हमें प्राप्त नहीं होती।

– श्री कैतल शाह – एसबीआईकैप सिक्योरटीज लिमिटेड.

– ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।

– समन्वयक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न एचएसबीसी के श्री असीम पंथ की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री असीम पंथ – एचएसबीसी

–धन्यवाद महोदय। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है।

– समन्वयक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न आईसीआईसीआई सिक्योरटीज के श्री हर्षिद तोसनीवाल की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– जी, महोदय। ये दोनों अनुवर्ती प्रश्न हैं। पहला, 23,000 करोड़ के एनपीए में से क्या आप आंकड़ों को दोहरा सकते हैं जो पिछले वर्षों में कमिशनिंग हुई और आगे के वर्षों में कितना अपग्रेड होगा?

– श्री राजीव शर्मा

– जी। यूनिट 1 और 2, मारवा टीपीएस।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– महोदय। मुझे एकदम सटीक जानकारी नहीं चाहिए। बस इतना बताएं कि 23,000 करोड़ का कितना हिस्सा कमीशन होने वाला है?

– श्री राजीव शर्मा

– 15,883 करोड़ जो पहले कमीशन हो चुके कार्य का लगभग 68 प्रतिशत है और इस वर्ष अपग्रेड हो जाएगा।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– जी और बकाया।

– श्री राजीव शर्मा

– 31 मार्च, 2018 तक 2 प्रतिशत या मोटे तौर पर 525 करोड़ की सीओडी प्राप्त कर ली जाएगी और यह रिवर्स भी हो जाएगी। 9 प्रतिशत या 2,096 करोड़ प्राप्त किया जाएगा और अपग्रेड कर पुनर्गठित हो जाएगी।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– जी। जिस 9 प्रतिशत का आपने जिक्र किया है वो कब कमिशन हो जाएगा?

– श्री राजीव शर्मा

– वित्त वर्ष 2017–18 में कमिशन और अपग्रेड हो जाएगा।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– किस वर्ष में महोदय, मैं सुन नहीं पाया।

– श्री राजीव शर्मा

– वित्त वर्ष 2017–18

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– जी। एक ओर बात। महोदय, कर्जदार–वार और पोर्टफोलियो–वार वर्गीकरण के लिए हमें 2022 तक छूट मिली हुई है।

– श्री राजीव शर्मा

– जी। यह क्रेडिट केंद्रण मानक है।

– श्री नागराजन

– दोनों वर्गीकरण में से एक क्रेडिट केंद्रण मानक की स्थिति में सीएमडी ने बताया कि हमने मार्च, 2022 तक छूट ले रखी है। इन दोनों परियोजनाओं की कमिशनिंग नहीं हो पाई है और डीसीसीओ में विलंब है। यहां भी हमें ऋण वार वर्गीकरण करना होगा जिसकी छूट 31 मार्च, 2022 तक है।

– श्री हर्षिद तोसनीवाल – आईसीआईसीआई सिक्योरटीज

– जी। इसे भी 2022 तक छूट प्राप्त होगी। ठीक है महोदय। धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– धन्यवाद।

– समन्वयक

– धन्यवाद। अगला प्रश्न डयूशे बैंक के श्री अभिषेक सराफ की ओर से है। कृपया प्रश्न पूछिए।

– श्री मनीष – डयूशे बैंक

– जी, मैं मनीष बोल रहा हूं। मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया है। आपका धन्यवाद।

– श्री राजीव शर्मा

– बहुत–बहुत धन्यवाद।

– समन्वयक

– धन्यवाद महोदय। यह अंतिम प्रश्न था। समापन टिप्पणियों के लिए, अब मैं मंच की कार्यवाही श्री शंकर को सौंपता हूं।

– श्री शंकर – प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड

– सभी प्रतिभागियों का बहुत–बहुत धन्यवाद। हमने काफी विस्तार से चर्चा की। पीएफसी के श्री राजीव शर्मा, श्री नागराजन, श्री रवि और श्री गंगोपाध्याय और समस्त प्रतिभागियों का धन्यवाद।

– साक्षात्कार

– बहुत–बहुत धन्यवाद।

– समन्वयक

– देवियों और सज्जनों आपका धन्यवाद। प्रभुदास लीलाधर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हम आज के सम्मेलन का समापन करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। आप अपनी लाइन डिसकनेक्ट कर सकते हैं।

****